PRGI. No.: MHMUL/25/A2419

पुपिल्स टाइम्स

PUPILS TIMES

Volume : 1 ▸ Issue : 18 ▸ Mumbai ▸ Friday, 05 June to 11 June 2026 ▸ Weekly ▸ Pages : 8 ▸ Price : 3 Rs.

जनजातीय विकास से ही बनेगा समावेशी भारत : राष्ट्रपति मुर्मु

नई दिल्ली: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास संस्थाओं (आईटीडीए) और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं (आईटीडीपी) को सुदृढ़ करने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने वर्चुअल माध्यम से भारतीय विज्ञान संस्थान के 'सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग' में 'ट्रेनिंग फैब' तथा 'एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों' में 75 'स्पेस लैब्स' का भी उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह सम्मेलन जनजातीय लोगों के जीवन में बदलाव लाने वालों का सम्मेलन है। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिभागियों का यह उत्तरदायित्व है कि वे जनजातीय समुदायों

के लिए संचालित कल्याणकारी और विकास कार्यक्रमों को सीधे गांवों और घरों तक पहुंचाएं। इससे जनजातीय समुदायों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि राज्य और परियोजना स्तर पर कार्य करने वाले लोग जब एक बड़े और साझा उद्देश्य के साथ विचार-विमर्श करेंगे, तो अनेक उपयोगी समाधान सामने आएंगे। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि सम्मेलन में जनजातीय विकास के विभिन्न महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा की जाएगी और इससे योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

शिक्षा और कौशल विकास को बताया सबसे महत्वपूर्ण

- द्रौपदी मुर्मु ने व्यक्ति और समाज की प्रगति में शिक्षा की भूमिका को रेखांकित करते हुए सभी हितधारकों से जनजातीय बच्चों और युवाओं की शिक्षा तथा कौशल विकास में पूर्ण समर्पण के साथ योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने प्रसन्नता जताई कि देशभर में लगभग 500 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं।

पीएम मोदी ने की डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली में वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें दोनों नेताओं ने भारत-वेनेजुएला संबंधों के पूर्ण स्पेक्ट्रम की समीक्षा की और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के रास्ते तलाशे। यह बैठक रोड्रिग्ज की भारत की पांच दिवसीय कामकाजी यात्रा के हिस्से के रूप में हैदराबाद हाउस में हुई, जो 3 जून को शुरू हुई। चर्चा ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित क्षेत्रों पर केंद्रित थी। विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों पक्ष ऊर्जा पर विशेष जोर देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा कर रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। भारत ऊर्जा क्षेत्र

में वेनेजुएला के साथ अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है, जबकि दोनों देश व्यापार, स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा में भी अवसर तलाश रहे हैं। यह यात्रा इस साल जनवरी में प्रधान मंत्री मोदी और रोड्रिगेज के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद हुई है, जिसके दौरान दोनों नेता कई क्षेत्रों में भारत-वेनेजुएला साझेदारी को और विस्तार और गहरा करने और वैश्विक दक्षिण के हित के मुद्दों पर सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए थे।

संक्षिप्त खबरें

भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का एशियाई देशों में क्रेज

नई दिल्ली: अचानक से एशियाई देशों में ब्रह्मोस मिसाइल का क्रेज पैदा हो गया है। इन देशों में चीन के पड़ोसियों का भी नाम शामिल है। असल में यह देश चीन की काट के तौर पर ब्रह्मोस को अपने बेड़े में शामिल करना चाहते हैं। यह पूरी कहानी का एक हिस्सा भर है। असली कहानी यह है कि रक्षा निर्यात में भारत का रुतबा लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2026 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यह अभी तक का सबसे सर्वोच्च स्तर है। पिछली बार से अब इसमें 62.66 फीसदी की उछाल आई है। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा मांग ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की है। हाल के दिनों में भारत ने विएतनाम और इंडोनेशिया के साथ इसके निर्यात को लेकर समझौता किया है। वहीं, फिलिपीन्स को वह पहले ही ब्रह्मोस बेच चुका है।

मुख्यमंत्री बनते ही डीके शिवकुमार ने किए बड़े एलान

छात्रों को फ्री बस पास और युवाओं को रोजगार देने का वादा

बंगलूरू: कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पद संभालने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े फैसलों का एलान किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य में विकास, रोजगार और किसानों के हितों को प्राथमिकता देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट बैठक में नए दौर की शुरूआत के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी नहीं बल्कि कर्नाटक की जनता की है और सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेगी। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने छात्रों और युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी छात्रों को फ्री बस पास दिया जाएगा ताकि पढ़ाई में आर्थिक परेशानी बाधा न बने। इसके साथ ही युवाओं को सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए जल्द ही कैलेंडर ऑफ इवेंट्स जारी किया जाएगा। **(शेष पेज-5 पर देखें)**

शिवकुमार ने क्या एलान किए?

- सभी छात्रों को फ्री बस पास देने का एलान।
- सरकारी नौकरियों के लिए जल्द भर्ती कैलेंडर जारी होगा।
- युवाओं के लिए प्राइवेट रोजगार एक्सचेंज बनाया जाएगा।
- रोजगार एक्सचेंज की रूपरेखा एक महीने में तैयार होगी।
- किसानों के पलायन को रोकने के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी।
- हर ग्राम पंचायत में 'भारत जोड़ो युवा संघ' को 10 लाख रुपये दिए जाएंगे।
- >> पूरे कर्नाटक में 10 हजार भारत जोड़ो युवा संघ बनाए जाएंगे।
- युवाओं में नेतृत्व क्षमता और सामाजिक सौहार्द बढ़ाने पर जोर।
- लोकतंत्र के चारों स्तंभों को मिलकर काम करने की अपील।

'आत्मनिर्भर भारत' की बड़ी तैयारी

नौसेना खरीदेगी पनडुब्बियां

नई दिल्ली: अब 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत नौसेना एक बार फिर मिनी पनडुब्बियां को लेकर आगे बढ़ रही है। मिनी पनडुब्बियां भारतीय नौसेना को तटीय क्षेत्रों, द्वीपीय इलाकों और संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों में विशेष अभियानों के लिए बड़ी रणनीतिक बढ़त देंगी। इन पनडुब्बियों का इस्तेमाल नौसेना के विशेष बल MARCOS (मरीन कमांडो) गुप्त अभियान, टोही मिशन और दुश्मन के इलाके में विशेष कार्रवाई के लिए करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, ये मिनी पनडुब्बियां 'स्विमर डिलीवरी व्हीकल' (SDV) या 'स्पेशल ऑपरेशंस वेसल' (SOV) के रूप में काम करेंगी। इनकी मदद से कमांडो समुद्र के भीतर से चुपचाप लक्ष्य के करीब पहुंच सकेंगे, मिशन को अंजाम देकर बिना किसी भनक के वापस लौट सकेंगे।

कैसी होती हैं मिनी पनडुब्बियां?

मिनी पनडुब्बियां सामान्य युद्धक पनडुब्बियों की तुलना में काफी छोटी होती हैं। इनका वजन करीब 150 से 550 टन तक हो सकता है और ये 8 से 20 कमांडो को ले जाने में सक्षम होती हैं। इनमें कम ध्वनि उत्पन्न करने वाली तकनीक, आधुनिक सेंसर और उथले समुद्री इलाकों में आसानी से संचालन की क्षमता होती है। भारत में ऐसी पनडुब्बियों की जरूरत पहली बार 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद महसूस की गई थी। हालांकि 2009 में शुरू हुई खरीद प्रक्रिया कई तकनीकी और साझेदारी संबंधी चुनौतियों के कारण आगे नहीं बढ़ सकी थी।

योगी कैबिनेट की मीटिंग में 24 प्रस्तावों को मंजूरी

किसानों-वकीलों और बस यात्रियों पर सरकार मेहरबान

लखनऊ: योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। जेल, परिवहन, कृषि और विधि विभाग से जुड़े बड़े फैसलों पर कैबिनेट ने हरी झंडी लगा दी। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रेस को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में एक ओर मक्का के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया तो दूसरी ओर सरकारी वकीलों का मेहताना जबरदस्त तरीके से बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में बस यात्रियों को तोहफा देते हुए 1725 नई बसों को चलाने का ऐलान किया गया है। जबकि विकास प्राधिकरणों

के क्षेत्र में पास किए गए जिला पंचायत के नक्शे को अब प्राधिकरण रेगुलर करेगा।

सरकारी वकीलों के मानदेय में बड़ा इजाफा : कैबिनेट ने जिला न्यायालयों में कार्यरत सरकारी वकीलों के मानदेय और भत्तों में 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके तहत रिटेनरशिप राशि और प्रति सुनवाई (हियरिंग) मिलने वाली फीस में भी उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडवोकेट्स को भी बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। वहीं, एडवोकेट जनरल की रिटेनरशिप 75 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे न्यायिक कार्यों में बेहतर दक्षता आएगी और सरकारी पक्ष को मजबूती मिलेगी। **(शेष पेज-5 पर देखें)**

संपादकीय

खेत बचाओ अभियान

यह अच्छा है कि पश्चिम एशिया संकट के चलते रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति में कठिनाई और उनके मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने खेत बचाओ अभियान शुरू किया। इस अभियान को शुरू करने के पहले केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों, आइसीएआर संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ कृषि अधिकारियों और किसान संगठनों से गहन संवाद किया, उससे यह पता चलता है कि वे इस अभियान को वास्तव में सफल होते हुए देखना चाहते हैं। ऐसे किसी अभियान की सफलता जन भागीदारी और जागरूकता के माध्यम से ही संभव है। निःसंदेह इस अभियान में केंद्र सरकार को राज्यों का सक्रिय सहयोग चाहिए होगा। इसी तरह यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि आम किसान यह समझें कि रासायनिक उर्वरकों का आवश्यकता से अधिक उपयोग केवल खेती की लागत ही नहीं बढ़ाता, बल्कि खेतों की मिट्टी की उर्वर क्षमता को भी कम करता है। इसके अतिरिक्त भूजल भी दूषित होता है। एक ऐसे समय जब जलवायु बदल रही है, तब उर्वरकों का असंतुलित उपयोग खेती के सामने गंभीर चुनौती बन रहा है। समस्या यह है कि औसत किसान यह समझ नहीं पा रहे हैं कि उर्वरकों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल अंततः उनके लिए घाटे का सौदा ही सिद्ध होता है, क्योंकि प्रारंभ में तो फसल अच्छी होती है, लेकिन समय के साथ खेतों की मिट्टी दूषित हो जाने के कारण उपज प्रभावित होती है। वैसे तो प्रधानमंत्री ऐसी अपील करते रहे हैं कि किसान रासायनिक उर्वरकों का सही उपयोग करने के लिए खेतों की मिट्टी का परीक्षण कराएं और जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ावा दें, लेकिन इसके बाद भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाए और रासायनिक खादों का अंधाधुंध उपयोग जारी है। इसका एक कारण उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी भी है। एक आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपये उर्वरक सब्सिडी पर खर्च किए। इस वर्ष यह खर्च कहीं अधिक बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि अधिकतर उर्वरकों का आयात किया जाता है और अमेरिका-ईरान तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनके मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा की मानें तो जहां दो बोरी उर्वरक के उपयोग की आवश्यकता होती है, वहां किसान चार बोरी का उपयोग करते हैं। वास्तव में जब भी कोई वस्तु सब्सिडी के चलते कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है तो उसका अनावश्यक उपयोग बढ़ जाता है। तथ्य यह भी है कि किसानों को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराए जाने वाले उर्वरक की कालाबाजारी भी होती है, क्योंकि उसका इस्तेमाल औद्योगिक रसायन के रूप में भी होता है।

अपराधियों पर हो ठोस कार्रवाई

अविश्वास से घिरती जा रहीं परीक्षाएं

देश में प्रश्नपत्रों का परीक्षा से पहले 'आउट' हो जाना लगभग सामान्य प्रक्रिया बन चुकी है। इसका विस्तार बोर्ड एवं प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षाओं तक फैल चुका है। सरकारी तंत्र ने अगले वर्ष के लिए सुधारों का आश्वासन दिया है। यह आवश्यक भी था, लेकिन जो अविश्वास पूरे देश में फैल चुका है, क्या उसका समाधान भी हो पाया है? अपराधियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। कुछ लोग तो वर्षों से इस प्रकार के अवैध कार्यों को व्यवसाय की तरह संचालित करते रहे हैं। निश्चित रूप से उन्हें कहीं न कहीं से संरक्षण भी मिलता रहा होगा। हर बार सरकारी तंत्र प्रश्नपत्र तैयार करने, उसे परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित पहुंचाने और परीक्षा प्रारंभ होने तक उसकी गोपनीयता बनाए रखने की व्यवस्था में सुधार करता है, लेकिन समस्या का एक बड़ा पक्ष ऐसा भी है, जिसे सभी जानते हैं, पर उसकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। कुछ वर्ष पहले बिहार की एक बोर्ड परीक्षा के परिणामों को लेकर देशव्यापी चर्चा हुई थी। उस दौरान एक छात्रा का यह कथन व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर करने वाला था कि 'मैं तो सेकेंड डिवीजन में पास होना चाहती थी, चाचा ने टाप करा दिया।' यह एक ऐसा संकेत था, जो समस्या के वास्तविक समाधान की दिशा दिखा सकता था। हमें इस पर भी विचार करना होगा कि आखिर लीक हुए प्रश्नपत्र कौन खरीदता है? इसके लिए धन तो परिवार ही देता है और साल्वर, वह भी नीट जैसी परीक्षा में, कौन बन सकता है? कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा छात्र या डाक्टर बन चुका सुशिक्षित व्यक्ति ही यह कार्य कर सकता है। क्या इस देश ने कभी नागरिकों को यह बताया कि किसी साल्वर को या बड़ी धनराशि देकर अपने लाड़लों के लिए प्रश्नपत्र खरीदने वाले परिवार के किसी सदस्य को क्या सजा मिली? इस प्रकार के मामलों और ऐसी अन्य कारगुजारियों में अपराधियों को दंडित करने के मामले में भारत इतना कमजोर क्यों है? या यूं कहें कि व्यवस्था इतनी शिथिल क्यों है? संविधान में मूलभूत कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। यदि सरकार, शिक्षित वर्ग और समाज इनका पालन करते होते तो क्या प्रश्नपत्र लीक होते? आगे क्या केवल कानून बदलकर प्रश्नपत्र लीक को रोका जा सकेगा? व्यवस्था को लगातार सतर्क तो रहना ही होगा, लेकिन जब तक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मानवीय तत्व को जागृत करने में असमर्थ रहेगी, तब तक ऐसी आशंकाएं साकार होती रहेंगी और परीक्षाओं की साख पुनः स्थापित नहीं हो पाएगी। नीट के प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच तेजी से चल रही है। यह स्पष्ट हो गया है कि जो लोग प्रश्नपत्र बनाने योग्य समझे गए थे, जो विशेषज्ञ माने जाते थे, वे अपेक्षित नैतिक स्तर पर खरे नहीं उतरे। विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष, एआइ और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के युवा किसी से पीछे नहीं हैं। फिर भी प्रश्न यह है कि हम परीक्षाओं को ईमानदारी और विश्वास के साथ संपन्न कराने में स्वयं को असमर्थ क्यों पाते हैं? एक महत्वपूर्ण पक्ष, जिस पर अपेक्षित चर्चा नहीं होती, वह है मनुष्य की बढ़ती स्वार्थपरकता, संग्रह की प्रवृत्ति और धन के निर्बाध दुरुपयोग का अहंकार। स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक इस विषय पर गंभीर वैचारिक मंथन की आवश्यकता है। ऐसी शिक्षा-पद्धति और विकल्पों की तलाश करनी होगी, जो केवल ज्ञान और कौशल ही नहीं, बल्कि नैतिकता से संपन्न व्यक्तित्व का भी निर्माण करें। साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी अपने जीवन के लक्ष्यों, सामाजिक दायित्वों और जनहित की समझ पर निरंतर आत्ममंथन करते रहना होगा। केवल आर्थिक और तकनीकी प्रगति पर्याप्त नहीं है। यदि उसके साथ नैतिक विकास नहीं जुड़ा होगा तो समाज और राष्ट्र दोनों ही गंभीर चुनौतियों का सामना करते रहेंगे।

भारतीय नौसेना कैसे समुद्र की सुरक्षा करती है

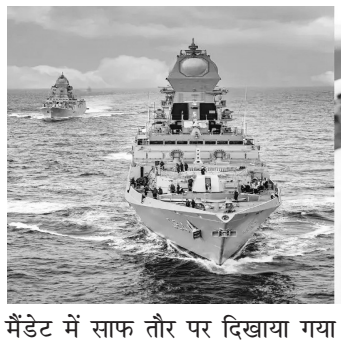

किसी देश की दौलत समुद्र पर लिखी होती है। भारत के लिए, हिंद महासागर का पानी कोई सरहद नहीं है, बल्कि उसके रोजाना के आर्थिक जीवन की जान है। एक मॉडर्न इकॉनमी पूरी तरह से फिजिकल चीजों के लगातार, बिना रुके आने-जाने पर निर्भर करती है। इस निर्भरता के मेट्रिक्स पक्के हैं और स्ट्रेटेजिक तरीके से पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। वॉल्यूम के हिसाब से भारत का 90 परसेंट से ज्यादा ट्रेड, और फाइनेंशियल वैल्यू के हिसाब से लगभग 70 परसेंट, समुद्र के पार होता है। बढ़ती फैक्ट्रियों और फैलते शहरों को चलाने के लिए जरूरी एनर्जी और भी जरूरी है। भारत का लगभग 80 परसेंट कच्चा तेल इंपोर्ट हिंद महासागर से होकर जाता है, जो संकरे, बहुत कमजोर स्ट्रेट से होकर जाता है। जब इन समुद्री रास्तों पर खतरा होता है, तो इंपोर्टेड चीजों की कीमत तुरंत बढ़ जाती है, और महंगाई का भारी बोझ आम नागरिक पर पड़ता है। इस जरूरी दौलत को सुरक्षित रखने के लिए, एक देश को ऐसी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे नकारा न जा सके। भारत ने सही मायने में एक रहने वाली समुद्री सुपरपावर की ज़िम्मेदारी ली है। यह राष्ट्रीय मकसद SAGAR मैंडेट में साफ तौर पर दिखाया गया है, जिसका मतलब है इस इलाके में सभी के लिए सिक्योरिटी और ग्रोथ। यह पॉलिसी ग्लोबल कॉमर्स की एक बुनियादी सच्चाई को मानती है: दूर के साथियों से पक्की सिक्योरिटी नहीं ली जा सकती। एक देश की ताकत के पास न सिर्फ अपने मर्चेंट फ्लीट की, बल्कि समुद्री व्यापार के बड़े, इंटरनेशनल रास्तों की भी सुरक्षा करने की फिजिकल कैपेसिटी होनी चाहिए। अपने देश में इकोनॉमिक ग्रोथ पक्का करने के लिए, समुद्र सभी के लिए सुरक्षित होना चाहिए। हमने हाल ही में देखा है कि यह समुद्री सुरक्षा कितनी जल्दी टूट सकती है। लाल सागर का संकट एक तेज और तुरंत मिसाल है। अचानक, मर्चेंट जहाजों को तट से किए गए एडवांस्ड, एसिमेट्रिक ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा, साथ ही सोमाली तट पर पारंपरिक पायरेसी का नया खतरा भी पैदा हो गया। इंडियन नेवी ने इस अफरा-तफरी का जवाब हिचकिचाहट से नहीं, बल्कि ऑपरेशन संकल्प की अहम ताकत से दिया। उन्होंने अरब सागर और अदन की खाड़ी में भारी हथियारों से लैस टास्क फोर्स तैनात कीं। इस आक्रामक कार्रवाई ने एक मॉडर्न सच्चाई साबित कर दी। ट्रेड की सुरक्षा के लिए अब हल्की पेट्रोल बोट्स काफी नहीं हैं। बहुत दूर तक मॉडर्न, एसिमेट्रिक खतरों का मुकाबला करने के लिए, नेवी को भारी, लगातार फोर्स तैनात करनी होगी। ग्लोबल सप्लाई चेन को चलाने वाले जरूरी मर्चेंट शिपिंग को बचाने का यही एकमात्र तरीका है। फिर भी, बिना साफ दिशा के कच्ची नेवी की ताकत बेकार है। समुद्र इतना बड़ा है कि सिर्फ. देखकर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। असरदार समुद्री ताकत के लिए अब जानकारी पर पूरी पकड़ जरूरी है।

अपने जीवन में परमेश्वर को वास्तविक बनाओ!

अगर आप एक नई शुरूआत करना चाहते हैं, एक नया इंसान बनना चाहते हैं, और अपनी ज़िंदगी की किताब में एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, तो भगवान को अपनी ज़िंदगी में बुलाएँ! अगर आप हमेशा भगवान के कॉन्टैक्ट में रहे हैं, तो उनसे अपना कॉन्टैक्ट फिर से शुरू करें। अगर आपने उनके साथ अपने खास रिश्ते को नजरअंदाज किया है, तो उन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस लाएँ। अगर आप भूलकर जी रहे हैं, तो अभी भी देर नहीं हुई है झ उन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस बुलाएँ। भगवान को अपनी ज़िंदगी में असली बनाने का क्या मतलब है? यह कोई अजनबी नहीं है जिसे आप अचानक 'कल्टीवेट' करने की कोशिश कर रहे हैं! भगवान कोई दूर की हस्ती नहीं हैं, जो कहीं ऊपर किसी धुंधले और दूर स्वर्ग में रहते हों! वह आपके अपने दिल की धड़कनों से भी ज्यादा करीब हैं, और आपके होने का उतना ही हिस्सा हैं जितना कि वह हवा जिसमें आप साँस लेते हैं! दिक्कत यह है कि हममें से कुछ लोग उन्हें हल्के में लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी दिल की धड़कनों और अपनी साँसों को हल्के में लेते हैं! मेडिटेशन जैसी टेक्नीक हमें अपनी साँसों के बारे में ज्यादा अवेयर, ज्यादा कॉन्शस बनाती हैं। इसी तरह, प्रार्थना भी हमें अपनी ज़िंदगी में उनकी लगातार मौजूदगी का एहसास करा सकती है। ज़िंदगी की भागदौड़ और रोजमर्रा के कामों में, हम अपने आस-पास भगवान की मौजूदगी को भूल जाते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी के हर पल उन्हें याद रखना होगा। हमें भगवान से जुड़ना होगा और उनकी मौजूदगी का अनुभव करना होगा। हमें अपने विश्वास पर पक्का रहना होगा। तब सच में, सब ठीक हो जाएगा, और हर तरह की चीजें ठीक हो जाएंगी।

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के बड़े फैसले

विश्वविद्यालय विस्तार और आर्थिक मंडलों में नई भर्तियों को मंजूरी

मुंबई: महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में हैदराबाद कॉलेजिएट समूह विश्वविद्यालय का विस्तार तथा तीन आर्थिक विकास मंडलों के लिए पदों की सृजन को मंजूरी देने का निर्णय। ये फैसले शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में प्रशासनिक सतर्कता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं।

निर्णय के अनुसार, मुंबई स्थित हैदराबाद (सिंध) नेशनल कॉलेजिएट समूह विश्वविद्यालय में अब पांच और महाविद्यालय घटक इकाई के रूप में जोड़े जाएंगे। इनमें प्राचार्य के. एम। कुंदनानी औषधि निर्माण शास्त्र महाविद्यालय, किशनचंद चेलाराम विधी महाविद्यालय, श्रीमती मीठीबाई मोतीराम कुंदनानी वाणिज्य एवं अर्थशास्त्र महाविद्यालय, ऋषी दयाराम और सेठ हसराम नेशनल विज्ञान महाविद्यालय तथा थडोमल शाहनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय शामिल हैं। परशुराम, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास मंडलों में व्यक्तिगत और समूह कर्ज व्याज परतावा (धनवापसी) योजनाएं चलाई जाती हैं। योजनाओं को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक मंडल में चार नियमित और पांच बाह्य स्रोत के पद बनाए गए हैं। नियमित पदों में प्रबंधकीय निदेशक, महाप्रबंधक, सहायक प्रबंधक (प्रशासन) तथा सहायक प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) शामिल हैं। तीनों मंडलों के लिए वार्षिक लगभग 1.18 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी गई है। साथ ही, मंत्रिमंडल ने यह भी स्पष्ट किया कि ये मंडल कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत सरकारी गारंटी वाली लेकिन बिना शेयर पूंजी वाली कंपनियां होंगी।

मंत्री दादाजी भुसे का बड़ा निर्देश

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से बढ़ेगा स्कूलों में नामांकन

मुंबई : महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने सरकारी स्कूलों का स्तर सुधार कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से छात्रों की संख्या (नामांकन) बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। मंत्रालय में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि जिला परिषदों के उत्कृष्ट स्कूलों का आदर्श लेकर सभी शासकीय स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाने के प्रयास तेज किए जाएं।

मंत्री भुसे ने कहा कि नए की शुरूआत में स्कूलों में प्रवेशोत्सव मनाकर छात्रों का उत्साहपूर्वक स्वागत किया जाएगा। इसी तरह स्कूल शुरू होने से पहले परिसरों की सफाई, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण यूनिफॉर्म और समय पर किताबें देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही स्कूलों में पीने का पानी, स्वच्छ शौचालय, रंग-

रोगन और छात्राओं के लिए 'पिंक रूम' की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

छात्र विकास और नामांकन वृद्धि : छात्रों में कला, संगीत, अभिनय और वक्तृत्व जैसे गुणों को निखारने के लिए जवाहर बालभवन की तर्ज पर गतिविधियां चलाई जाएंगी। स्कूलों के विकास के लिए पूर्व छात्र संघ और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड की मदद ली जाएगी। इसके अलावा, आंगनबाड़ियों को जिला परिषद स्कूलों के परिसर में शुरू किया जाएगा, जिससे भविष्य में प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मराठी अनिवार्य : राज्य के सभी माध्यमों और प्रबंधनों के स्कूलों में मराठी भाषा पढ़ाना अनिवार्य होगा और इसे कड़ाई से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही स्कूलों में 'एक पेड़ मां के नाम' वृक्षारोपण अभियान प्रभावी रूप से चलाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में शिक्षकों के रिक्त पदों को समय पर भरने और छात्र सुरक्षा योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने की बात भी कही गई।

विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू होगा ग्रीन मुंबई अभियान

मुंबई: मुंबई की महापौर रितू तावड़े ने वाशी नाका और ऐरोली नाका क्षेत्रों का दौरा कर इन स्थानों पर व्यापक हरित क्षेत्र विकास का खाका तैयार करने के निर्देश दिए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को इस अभियान की प्रतीकात्मक शुरूआत पौधारोपण के साथ की जाएगी। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दोनों प्रवेश मार्गों के आसपास राजमार्ग के दोनों ओर हरित पट्टियां विकसित की जाएं। इसके लिए अनावश्यक झाड़ियों और खरपतवारों को हटाकर क्षेत्र को स्वच्छ बनाया जाए तथा सुनियोजित तरीके से वृक्षारोपण किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से फूलदार और छायादार वृक्षों की बड़े पैमाने पर रोपाई करने पर जोर दिया, ताकि शहर में प्रवेश करने वाले लोगों को हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव हो सके।

निरीक्षण के दौरान महापौर ने पंतनगर से मुलुंड तक पूर्वी द्रुतगति मार्ग के खाड़ी किनारे स्थित खाली स्थानों पर पीले अमलतास (बहावा) के वृक्ष लगाने का विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। यह अभियान एन, एस और टी प्रशासनिक विभागों के संयुक्त प्रयास से संचालित किया जाएगा।

जलभराव रोकने के लिए नाला सफाई में तेजी के निर्देश : मुंबई में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए बीएमसी ने नाला सफाई और गाद निकासी कार्यों को तेज करने का निर्णय लिया है। महापौर रितु तावड़े ने परिमंडल-5 के विभिन्न नालों और जलनिकासी परियोजनाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जहां आवश्यकता हो, वहां अतिरिक्त मानवबल और मशीनरी तैनात कर कार्यों को निर्धारित समय में पूरा किया जाए, निरीक्षण के दौरान महापौर ने घाटकोपर (पूर्व) के जय अंबे नगर स्थित सोमैया नाला, गोवंडी के सुभाष नगर नाला, चेंबूर के वाशी नाका नाला, जिजामाता नगर कल्वर्ट, आर सी। मार्ग के समीप स्थित नाला तथा अयोध्या नगर के मानसिंह विजय सोसायटी क्षेत्र के नाले का दौरा किया। इन स्थानों पर चल रहे गाद निकासी कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को कार्यों में किसी प्रकार की ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए। महापौर ने विशेष रूप से उन निचले इलाकों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा जहां भारी बारिश के दौरान पानी भरने की संभावना अधिक रहती है।

राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे की बड़ी घोषणा

10 दिनों में किसानों को मिलेगी कर्ज माफी

मुंबई: पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होलकर की 301वीं जयंती के अवसर पर अहिल्यानगर के चौंडी में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगले 8 से 10 दिनों के भीतर किसानों की कर्जमाफी की घोषणा कर दी जाएगी। कृषि मंत्री भरणे ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार की अनुमति से यह घोषणा की जा रही है। राज्य सरकार ने ह्यपुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर कर्जमाफी योजनाह्न के तहत दो लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने का निर्णय लिया है। इससे 24 लाख 73 हजार से अधिक बकाएदार किसानों को लाभ मिलेगा। मंत्री भरणे ने बताया कि चौंडी गांव और आसपास के विकास के लिए करीब 1200 से 1300 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। अगले दो-तीन वर्षों में इस क्षेत्र की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। उन्होंने अहिल्यादेवी के जलसंधारण कार्यों को भी याद

किया और कहा कि एक ब्रिटिश लेखक के अनुसार विश्व की महान स्त्रियों में अहिल्यादेवी होलकर का नाम प्रथम आता है। कृषि मंत्री ने यह भी घोषणा की कि गडेरिया (मेढपाल) और धनगर समाज के युवाओं के लिए कृषि विभाग की ओर से एक विशेष योजना लाई जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस योजना पर काम चल रहा है, जिससे समाज के युवकों को बड़ा फायदा होगा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, विधान परिषद के सभापती राम शिंदे, पूर्व मंत्री अन्नासाहेब डांगे, एमएलए गोपीचंद पडलकर, सुनील कर्जतकर, रामराव वडकुटे, उत्तमराव जानकर सहित कई अन्य नेता उपस्थित थे।

मुंबई के 'पे एंड यूज' शौचालयों पर बीएमसी सख्त

>> 90 दिनों में सुधार नहीं तो रद्द होगा ठेका

मुंबई: मुंबई में सार्वजनिक शौचालयों की गुणवत्ता सुधारने के लिए बीएमसी ने सख्त रुख अपनाया है। मनपा में सभागृह नेता गणेश खणकर की अध्यक्षता हुई बैठक में 'पे एंड यूज' शौचालयों का संचालन करने वाली संस्थाओं को 90 दिनों के भीतर स्वच्छता, रखरखाव और मूलभूत सुविधाओं में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही सभी शौचालयों में फीडबैक सिस्टम और आईओटी आधारित दुर्गंध निगरानी व्यवस्था अनिवार्य की गई है। मनपा की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समयावधि में मानक पूरे नहीं करने वाले संचालकों के ठेका रद्द किए जा सकते हैं। मनपा में सभागृह नेता गणेश खणकर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उपायुक्त घनकचरा प्रबंधन किरण दिघावकर,

परिमंडल सात के उपायुक्त मनीष, नगरसेवक सिद्धांत शर्मा, आर दक्षिण की सहायक आयुक्त आरती गोलेकर, आर मध्य के सहायक आयुक्त प्रफुल्ल तांबे, घनकचरा प्रबंधन व अनुरक्षण विभाग के अधिकारी और विभिन्न सार्वजनिक शौचालयों का संचालन करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में यह पाया गया कि कई सार्वजनिक शौचालयों में मूलभूत सुविधाओं, स्वच्छता और रखरखाव के स्तर में सुधार की आवश्यकता है।

प्यूपिल्स टाइम्स

'देवाभाऊ' ने दी महा कर्जमाफी

चुनाव के बाद मिलेगा लाभ, 56 लाख किसानों को मिलेगी राहत

मुंबईः 'देवाभाऊ' के उपनाम से लोकप्रिय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अन्नदाता किसानों को 'महा कर्जमाफी' का तोहफा दिया है। मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमाफी योजना' को मंजूरी दे दी गई, हालांकि विधान परिषद चुनाव की आचार संहिता के कारण इसकी आधिकारिक घोषणा चुनाव के बाद ही होगी। मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में राज्य के 36 जिलों के लगभग 56 लाख किसानों के दो लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के दायरे में 65 लाख से अधिक ऋण खाते आएंगे और सरकार पर करीब 36 हजार 585 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। यह महायुति गठबंधन का 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले किया गया प्रमुख वादा था, जिसे

अब पूरा किया गया है। लेकिन मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बावजूद योजना की सार्वजनिक घोषणा अभी नहीं की गई है, क्योंकि विधान परिषद चुनाव के चलते आचार संहिता लागू है। चुनाव आयोग के नियमों के तहत आचार संहिता के दौरान सरकार बड़े नीतिगत फैसलों की सार्वजनिक घोषणा नहीं कर सकती।

नियमित कर्ज चुकाने वालों को बोनस : सरकार ने केवल बकाएदार किसानों को ही नहीं, बल्कि नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों को भी 50 हजार रुपए तक का प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। योजना में 30 सितंबर 2025 तक के बकाया कृषि ऋण शामिल किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य जून के अंत तक कर्जमाफी की राशि किसानों के खातों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू करने का है। कर्जमाफी के लिए पात्रता के मापदंडों को पिछली सफल योजनाओं की तरह ही सरल और पारदर्शी रखा जा रहा है ताकि वास्तविक जरूरतमंदों तक मदद पहुंच सके।

कृषि संकट के बीच ऐतिहासिक फैसला : महाराष्ट्र लंबे समय से किसान आत्महत्याओं और कृषि संकट की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में यह निर्णय किसानों और विभिन्न किसान संगठनों के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। कर्ज के बोझ तले दबे किसानों को इस योजना से आर्थिक राहत मिलने और कृषि क्षेत्र में स्थिरता आने की उम्मीद है।

पात्रता मानदंड और कर्ज मुक्ति का स्वरूप : इस योजना के अंतर्गत 30 सितंबर 2025 तक के बकाया कृषि ऋणों को शामिल किया गया है, जिसमें कर्ज मुक्ति, वन टाईम सेटलमेंट और प्रोत्साहनपर लाभ के तीन घटक होंगे। दो लाख रुपए से कम कर्ज वाले किसान पूरी तरह कर्ज मुक्त होंगे। हालांकि, राजनीतिक पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, आयकर पात्र व्यक्ति और सहकारी संस्थाओं के 25 हजार रुपए से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी इस कर्जमाफी के लिए पात्र नहीं होंगे।

वनटाईम सेटलमेंट और प्रोत्साहनपर लाभ : जिन किसानों का कर्ज दो लाख रुपए से अधिक है, उन्हें ह्यवन टाईम सेटलमेंटह्व के तहत दो लाख से ऊपर की बकाया राशि 31 मार्च 2027 तक बैंक में जमा करनी होगी, जिसके बाद शासन उनके खाते में दो लाख रुपए जमा करेगा।

इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों में नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले ईमानदार किसानों को प्रोत्साहन के रूप में अधिकतम 50 हजार रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य जून महीने के अंत तक राहत राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर करने का है, जो गंभीर कृषि संकट और आत्महत्याओं के बीच जूझ रहे ग्रामीण क्षेत्र के लिए संजीवनी साबित होगी।

757 ग्रामीण मराठी स्कूलों पर नहीं चलेगी सरकार की कैंची

मुंबईः महाराष्ट्र सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने अप्रैल 2026 की शुरूआत में एक ऐसा कदम उठाया था, जिससे राज्य के सैकड़ों गैर-सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अस्तित्व पर ही संकट मंडराने लगा था। 1 और 2 अप्रैल, 2026 को जारी किए गए दो अलग-अलग सरकारी प्रस्तावों के माध्यम से राज्य के 757 स्कूलों को वित्तीय अनुदान सूची से बाहर (अपात्र) कर दिया गया था। सरकार के इस अप्रत्याशित रुख के कारण स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया था। शिक्षक संघों ने आशंका जताई थी कि वित्तीय सहायता रुकने से ग्रामीण इलाकों के ये स्कूल बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद इस फैसले को अदालत में चुनौती दी गई।

इस संवेदनशील मामले पर विस्तार से सुनवाई करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय की कोल्हापुर बेंच के माननीय न्यायमूर्ति माधव जे. जामदार और न्यायमूर्ति प्रवीण एस. पाटिल की खंडपीठ ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। अदालत ने बेहद कड़े शब्दों में टिप्पणी की कि किसी भी संस्थान को अपना पक्ष रखने या स्पष्टीकरण देने का मौका दिए बिना सीधे

अपात्र घोषित कर देना प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है। सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार की दोहरी नीति पर भी तंज कसा। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि एक तरफ तो राज्य सरकार मराठी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बड़े-बड़े कदम उठाने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे प्रशासनिक निर्णय लिए जा रहे हैं जिससे ग्रामीण इलाकों के मराठी माध्यम के स्कूलों में भारी भ्रम और डर की स्थिति पैदा हो रही है। पीठ ने याद दिलाया कि इस तरह के फैसलों का सबसे सीधा और गंभीर असर ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों के गरीब छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के भविष्य पर पड़ता है।

अपात्र स्कूलों की सूची से तुरंत नाम हटाने का आदेश

अदालत ने प्रभावित स्कूलों के पक्ष में अंतरिम निर्देश जारी करते हुए कहा है कि याचिका दायर करने वाले सभी विद्यालयों के नाम अपात्रता की सूची से तुरंत प्रभाव से हटाए जाएं। जब तक शिक्षा विभाग इन सभी स्कूलों की व्यक्तिगत स्तर पर विधिवत सुनवाई पूरी नहीं कर लेता, तब तक ये सभी 757 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय पहले की तरह ही सामान्य रूप से काम करते रहेंगे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की वित्तीय या प्रशासनिक दंडात्मक कार्रवाई पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

स्कूल प्रबंधन और शिक्षक संगठनों ने जताई खुशी

बॉम्बे उच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक और राहत भरे फैसले का महाराष्ट्र के विभिन्न शिक्षक संघों, स्कूल प्रिंसिपलों और शिक्षाविदों ने खुले दिल से स्वागत किया है। प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि अदालत समय रहते हस्तक्षेप नहीं करती, तो दूर-दराज के गांवों में पढ़ रहे हजारों जरूरतमंद बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हो जाते। अब सभी स्कूल प्रबंधन सरकार के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अपना पूरा पक्ष और आवश्यक दस्तावेज मजबूती के साथ पेश करने की तैयारी में जुट गए हैं।

ठाणे में शुरू होगा पहला मनपा सीबीएसई स्कूल

8 जून से छात्रों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा और आधुनिक सुविधाएं

गौरव सिंह/नवी मुंबई

ठाणेः ठाणे महानगरपालिका का पहला सीबीएसई बोर्ड स्कूल 8 जून से खारेगांव में शुरू हो रहा है। 'ठाणे मनपा-क्रिस्टल हाउस' सीबीएसई बोर्ड स्कूल क्रिस्टल हाउस इंडिया के साथ मिलकर चलाया जाएगा और इस स्कूल के जरिए विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा, आधुनिक सुविधाएं और हर तरह के विकास के मौके उपलब्ध कराए जाएंगे। मनपा आयुक्त सौरभ राव ने मंगलवार अधिकारियों के साथ बैठक कर इस स्कूल के कामकाज की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। खारेगांव में सफायर हॉस्पिटल के पास 'ठाणे मनपा-क्रिस्टल हाउस स्कूल' है। मनपा की तरफ से स्कूल के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें लाइब्रेरी, साइंस लैबोरेटरी, कंप्यूटर रूम, लैंग्वेज लैबोरेटरी, स्पोर्ट्स और आर्ट डिपार्टमेंट के लिए अलग जगह, पीने का साफ पानी, टॉयलेट, साथ ही बिल्डिंग की मरम्मत, पेंटिंग, लिफ्ट, सीसीटीवी सिस्टम और आग बुझाने का सिस्टम लगाना शामिल है। क्रिस्टल हाउस प्रबंधन की जिम्मेदारियों में ट्रेंड टीचर और नॉन-टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति, प्री-प्राइमरी से 12वीं तक के विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा, यूनिफॉर्म, किताबें और पढ़ाई का सामान उपलब्ध करना, विद्यार्थियों के खाने का इंतजाम और स्कूल तक ट्रांसपोर्ट की सुविधा देना शामिल है। इसके अलावा, विद्यार्थियों को हायर एजुकेशन, करियर गाइडेंस और नौकरी दिलाने वाली ट्रेनिंग देने पर भी जोर दिया जाएगा। फि लहाल नर्सरी से सेकेंडरी तक की कक्षाएं शुरू की जाएंगी।

Result Guarantee Above 90% or Money Back
If U R Not Joining Home Tuitions Then U R Missing Many Things
Mumbai's No.1 Premium Home Tuitions Academy
MUMBAI HOME & PRIVATE TUITIONS
1st to 10th ICSE / CBSE / IB / IGCSE / NIOS / State Boards
XI & XII Sci / Comm. IIT, NEET, MHT-CET
Engg, Degree, Diploma, B.Com, Bsc., BMS, MBA, Gmat, Cat, CET, English Speaking
Rajendra Deshmukh MANAGING DIRECTOR
Any Class Home Tuitions Across Mumbai
Get Admission in MBBS
NEET Qualified / Unqualified Fees 25 Lacs (Inc. Food Acc.)
ADMISSIONS OPEN
Branches : Andheri - Worli - Jogeshwari - Malad - Dadar - Borivali - Virar Thane - Vashi - Nerul - Kharghar - Ambernath - Badlapur
Home Tuitions Benefits
1. We get personal attention but in class its not there. 4. Its Time saving but in classes time wasted. 2. We get Result guarranty but classes no result guarranty. 5. Here efficiency 10 times more than classes in classes low efficiency. 3. Syllabus Completion in our hand in classes we cannot complete in our time. 6. Class Time as per students convenience, in classes as per their time
Contact : 902 902 9222 / 80 80 80 34 12 / 8446642380 / 9209128153
https://www.mumbaihometutors.com

PRIME KEYS PROPERTIES
Beyond Dreams
BUY | SELL | RENT
FLATS • SHOPS • BUNGALOWS
LANDS • REDEVELOPMENT
Trusted Property Consultant
Residential & Commercial Deals
Best Market Price Assistance
Contact:
+91 9167378057
Your Dream Property, Our Priority

DR. ZUBER SHAH HOSPITAL & POLYCLINIC
Ambernath (W), Maharashtra
Nursing Home Reg. No.: THN-C274*
FACILITIES AVAILABLE
24x7 Emergency Care - Immediate Critical Support
Diabetology & Advanced Diabetic Care
Fever Treatment (Dengue, Chikungunya, Malaria, Influenza)
Cardiology Checkup & ECG Facility
General Medicine Consultation
Vaccination & Immunization Services
Minor Surgical Procedures
OPD & IPD Care Available
Complete Health Checkups
24 HOURS EMERGENCY SERVICE AVAILABLE
DR. ZUBER S. SHAH
M.B.B.S (Reg. No. 2024020955)
Cert. in Diabetology & Emergency Medicine
+91 9323594085 / 8237304085 | Buvapada, K B Road, Ward No. 2/2, Ambernath West, Thane,
Woolen Chawl OPD : 8:00 pm to 11:30 pm | OPD Amber Care : 8149477110

स्वास्थ्य के लिए क्यों जरूरी है विटामिन-सी और विटामिन-डी

■ डॉ. आशीष मिश्रा
श्रीराम पॉलिक्लिनिक व आयुर्वेदिक दवाखाना

कई अध्ययन इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर आपकी इम्युनिटी ठीक है तो कई बीमारियों का खतरा टल सकता है। विशेषतौर पर वायरस, बैक्टीरिया और दूसरे संक्रमणों के कारण होने वाली दिक्कतों से आप काफी हद तक बचे रह सकते हैं। हालांकि चिंताजनक रूप से जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल और खान-पान में गड़बड़ी बढ़ती जा रही है, इसने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। यही वजह है कि अब लोगों में बार-बार सर्दी-जुकाम, थकान, संक्रमण और कमजोरी जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान भी बीमारी से बचे रहने के लिए अपनी इम्युनिटी को मजबूत रखने वाले उपाय करते रहने की सलाह दी जा रही थी। इसके लिए पोषक तत्वों, विशेषकर विटामिन-सी और विटामिन-डी वाली चीजों के सेवन को सबसे जरूरी माना जाता है। ये दोनों ही शरीर के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व हैं।

विटामिन-सी इम्युनिटी के लिए जरूरी

विटामिन-सी को सेहत के लिए जरूरी माना जाता है, इसे इम्युनिटी बूस्टर माना जाता है। अध्ययनों में पाया गया है कि पर्याप्त मात्रा में विटामिन-सी लेने से सर्दी-जुकाम की अवधि कुछ हद तक कम हो सकती है।

>> यह पानी में घुलने वाला विटामिन है, जो शरीर में स्टोर नहीं होता इसलिए रोजाना इसकी जरूरत पड़ती है।

>> विटामिन-सी शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, जिससे शरीर संक्रमण से बेहतर तरीके से लड़ पाता है।

>> विटामिन-सी एक प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को कम करता है।

विटामिन-डी में बीमारियों से लड़ने की क्षमता

धूप के संपर्क में आने से विटामिन-डी का निर्माण होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि विटामिन-डी केवल हड्डियों के लिए ही नहीं बल्कि इम्युनिटी के लिए भी बेहद जरूरी है। जिन लोगों में विटामिन-डी की कमी होती है, उनमें श्वसन संक्रमण, फ्लू और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। घर के अंदर ज्यादा रहने वाले लोगों और धूप कम लेने वालों में इसकी कमी ज्यादा देखी जाती है।

>> विटामिन-डी शरीर की टी-सेल्स और दूसरे इम्यून सेल्स को एक्टिव करने में मदद करता है।

>> ये सेल्स वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

>> विटामिन-डी इंफ्लेमेशन को नियंत्रित करने में भी मदद करता है, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया संतुलित रहती है।

'यह परिशिष्ट किसी एक मत या संप्रदाय का प्रचार नहीं, बल्कि मानवता, नैतिकता, आध्यात्मिकता और सहअस्तित्व के सार्वभौमिक मूल्यों का मंच है।'

'आध्यात्मिक संवाद'

इन चीजों से प्रसन्न होते हैं लड्डू गोपाल

भोग लगाने पर जीवन में आएंगे सकारात्मक बदलाव

हिंदू धर्म में भगवान श्रीकृष्ण की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। प्रभु की कृपा और उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्तजन पूरे विधि-विधान से उनकी उपासना व उनकी सेवा करते हैं। इस दौरान कुछ लोग भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी को घर में भी रखे हैं। उनकी सेवा बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह प्रेम और श्रद्धा के साथ की जाती है। मान्यता है कि, लड्डू गोपाल जी की नियमित पूजा-अर्चना और सच्चे मन से की गई सेवा से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भक्त उन्हें प्रतिदिन स्नान, वस्त्र और श्रृंगार के साथ प्रिय भोग भी अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि, प्रेम और श्रद्धा से लगाया गया भोग भगवान श्रीकृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है और इससे उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती हैं। ऐसे में आइए प्रभु के प्रिय भोग और उससे मिलने वाले लाभ को जानते हैं।

माखन-मिश्री का भोग : भगवान श्रीकृष्ण को माखन-मिश्री बेहद प्रिय है। ऐसे में यदि श्रद्धा से माखन और मिश्री का भोग लगाया जाए, तो माना जाता है कि प्रभु प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। साथ ही जीवन में कई अच्छे बदलाव महसूस होते हैं।

खीर-रबड़ी अर्पित करें : कान्हा जी को दूध से बनी चीजें बहुत प्रिय मानी जाती हैं। ऐसे में खीर या रबड़ी का भोग लगाना बेहद शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इससे जीवन में आ रही बाधाएं धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं। साथ ही लंबे समय से रुके कार्य पूरे होने के योग बनते हैं।

मिठाइयों का भोग : भगवान कृष्ण को मीठे व्यंजन अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। आप पेड़ा, बेसन के लड्डू या मखाने के लड्डू का भोग लगा सकते हैं। इससे परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। इसके अलावा प्रभु भी प्रसन्न होते हैं।

पंजीरी : लड्डू गोपाल जी को पंजीरी अर्पित करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह भोग सकारात्मक ऊर्जा और घर में शुभता बढ़ाने वाला माना जाता है।

पंचामृत का महत्व : दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से तैयार पंचामृत भगवान कृष्ण को अर्पित करने से मानसिक शांति मिलती है। पूजा के बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना भी शुभ माना जाता है।

ताजा दूध का भोग : श्रीकृष्ण का संबंध गौसेवा और दूध से जुड़ा हुआ है। ऐसे में उन्हें दूध अर्पित करना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

कलियुग की विषमता और भगवन्नाम का शाश्वत आश्रय

श्रीमद्भागवत महापुराण में कलियुग की विकट परिस्थितियों का अत्यंत मार्मिक वर्णन मिलता है।

अनावृष्ट्या विनङ्क्ष्यन्ति दुर्भिक्षकरपीडिताः।
शीतवातातपप्रावृड् हिमैरन्योन्यतः प्रजाः॥

अर्थात समय पर वर्षा न होने से अकाल और आर्थिक संकट उत्पन्न होंगे। प्रजा कभी अत्यधिक शीत, कभी प्रचण्ड गर्मी, कभी आँधी-वर्षा और प्राकृतिक असंतुलन से पीड़ित रहेगी। केवल प्रकृति ही नहीं, बल्कि स्वार्थ, वैर और नैतिक पतन के कारण मनुष्य भी एक-दूसरे के दुःख का कारण बनेंगे। यह श्लोक संकेत देता है कि जब धर्म, संयम और सदाचार क्षीण होते हैं, तब समाज और प्रकृति दोनों का संतुलन डगमगा जाता है। ऐसे समय में शास्त्र एक ही स्थायी मार्ग बताते हैं भगवन्नाम का आश्रय।

अब प्रभु कृपा करहु एहि भाँति।
सब तजि भजनु करौं दिन राती॥

कलियुग में हरिनाम-स्मरण ही मनुष्य को शांति, धैर्य और आध्यात्मिक स्थिरता प्रदान करने वाला सर्वोत्तम साधन है।

पेज-1 का शेष

योगी कैबिनेट की मीटिंग में 24 प्रस्तावों को मंजूरी...

वाहन स्वामियों को मिली राहत : कैबिनेट बैठक में लाखों वाहन स्वामियों को राहत देने वाला एक अहम फैसला भी लिया गया. हालांकि इसके विस्तृत प्रावधानों की जानकारी बाद में जारी की जाएगी, लेकिन माना जा रहा है कि इस निर्णय से बड़ी संख्या में वाहन मालिकों को सीधा लाभ मिलेगा.

इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा : राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है. कैबिनेट ने 18 शहरों में जीसीसी (ऋऊउ) मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दी है. इसके अलावा बड़े शहरों में वातानुकूलित (अउ) इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई है. सरकार का उद्देश्य प्रदूषण कम करना और यात्रियों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है.

जेल और आधारभूत ढांचे से जुड़े फैसले : कैबिनेट ने जेलों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी. जेलों में बंदियों की मृत्यु होने पर मुआवजा देने की नई नीति को स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके साथ ही पांच जिलों में नई जेलों के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है. मोहनलालगंज में नए रजिस्ट्री कार्यालय के निर्माण के लिए जमीन आवंटन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई. इससे क्षेत्र के लोगों को रजिस्ट्री संबंधी कार्यों में सुविधा मिलेगी.

कई विभागों के प्रस्तावों पर मुहर: कैबिनेट बैठक में खाद्य, कारागार, सिंचाई, आबकारी और परिवहन समेत विभिन्न विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. सरकार का कहना है कि इन फैसलों से किसानों, कर्मचारियों, आम नागरिकों और सार्वजनिक सेवाओं को लाभ मिलेगा तथा विकास कार्यों को गति मिलेगी.

मुख्यमंत्री बनते ही डीके शिवकुमार ने किए बड़े एलान...

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए निजी रोजगार विनिमय केंद्र भी शुरू करेगी, जहां लोग अपना पंजीकरण करा सकेंगे। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार एक निजी रोजगार एक्सचेंज बनाएगी, जिससे निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वाले युवाओं को मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना की रूपरेखा एक महीने के भीतर तैयार कर ली जाएगी। सरकार का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को सही जानकारी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

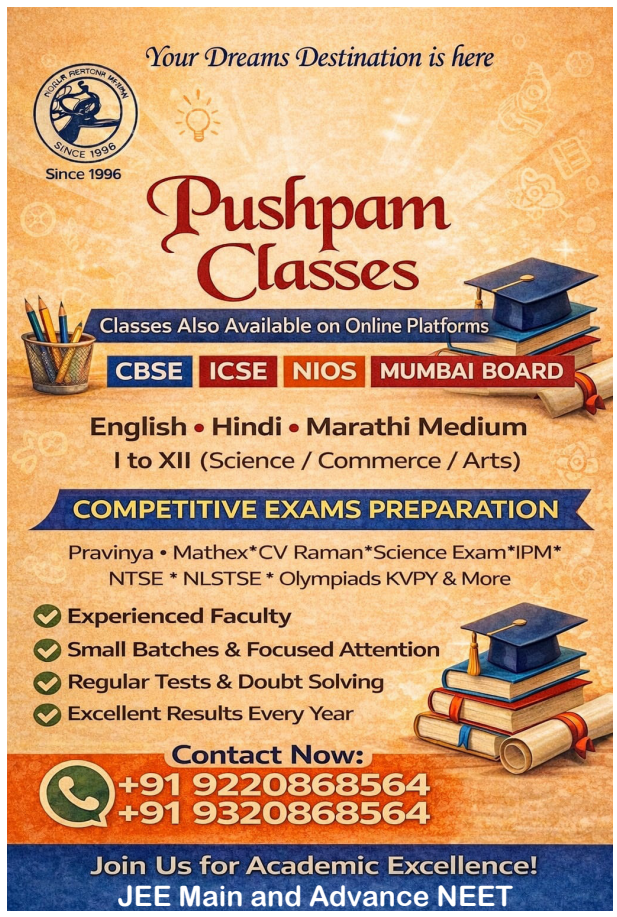

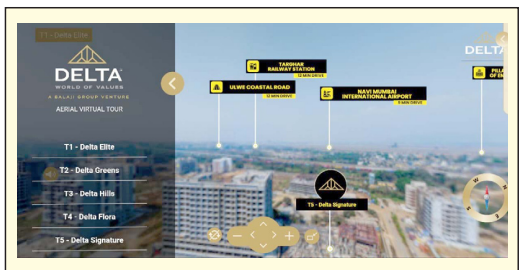

Step into the Future with ASR Digi!

Imagine exploring properties, products, and places without leaving your home! With our state-of-the-art Virtual Reality Tours, your audience can experience your offerings like never before.

Our Services Include:
- Immersive Virtual Tours
- Captivating Drone Videography
- Realistic 3D Renders
- Scale Models
- Influencer & YouTube Marketing
- Professional Website Development
- Side Branding with LED Screens

Don't just tell your Story-show it in stunning detail!

Contact us today!
Satish Pandey from Navi Mumbai
8879895829 / 9619574572
www.asrdigi.com

नगण्यम् यदा 'एकस्य' मूल्यं शून्यीक्रियते

Dr. Vandana Mishra
M. A. NET (JRF) PHD

पात्राणि: 'तथ्यः' सूत्रधारः। **'नियतः'** नगर-सेवकः। **'नियमः'** विकास-ठेकेदारः। **'नगः'** श्रमिकः। **'धारा'** नागरिकः। **'अन्तिमः'** नगरस्य अन्तिमः वृक्षः। **'आँकडा'** 'नगर-प्रबन्धन-तन्त्रस्य' कृत्रिमा वाणी। **'चीत्कारः'** पक्षि-समूहः। **'तमाशा'** वार्ता-वाहकः।

प्रस्तावना

आँकडाः सुप्रभातम्। वायु-गुणवत्ता-सूचकाङ्कः 'असन्तोषजनकः'। हरित-अद्यतनम् 'अन्तिमः' इत्यस्य आयुः द्वादश निमेषाः। दक्षतायै निष्कासनम् अनुशंसितम्।

तथ्यः: 'नगण्यम्' इत्यत्र भवतां स्वागतम्। इदं न्यायालयः न 'जन-सुनवायी' अस्ति। अत्र कोऽपि खलनायकः नास्ति केवलं 'हितधारकाः' सन्ति।

नियतः: एते विहगाः किमर्थम् एवं कोलाहलं कुर्वन्ति? वार्षिक-विवरणं तु 'विकास-दरः 8%' इति वदति!

चीत्कारः: पलायध्वम्! 'नगः' आगतः! करपत्रेण सह! 'अन्तिमः' अपि अधुना न भविष्यति!

अङ्कः 1: अनुमतेः अभिशापः

नगः: मार्गं ददातु 'नियत' महोदय। 'नियमस्य' 'कार्य-आदेशः' अस्ति। मार्गः विस्तारणीयः।

नियतः: परन्तु 'अन्तिमः'.. अयं नगरस्य स्मृति-स्तम्भः! अस्मिन् एव मम जनन्या दोला बन्धिता आसीत्!

नियमः: भावुकता अनुचिता महोदय। 'जन-हित-मूल्याङ्कनस्य' पृष्ठं 247। कृपया पठतु।

नियतः: '...एकस्य वृक्षस्य क्षतिः नगण्या मन्तव्या।'

नगः: '...एकस्य वृक्षस्य क्षतिः नगण्या मन्तव्या।'

तथ्यः: '...एकस्य वृक्षस्य क्षतिः नगण्या मन्तव्या।' पश्यन्तु! 'नगण्यम्' इदानीं प्रशासनिक-मन्त्रः जातः। दिने त्रिवारं जपत अन्तरात्मा भार-मुक्तः।

नगः: महोदय मन्त्राः पश्चात्। दैनिकी पञ्चशतं रूप्यकाणि। वृक्षः पतति चेत् चुल्ली ज्वलति। न पतति चेत् इदम् उदरं 'नगण्यं' भविष्यति।

नियतः: किं करोमि अहम्? 'नियतः' नाम मम परन्तु 'निर्णयः' मम कुत्र?

अङ्कः 2: अन्तिमस्य अभियोगः

अन्तिमः: अहम् 'अन्तिमः'। हरित-अङ्कः 0.0001। 'आँकडा' इत्यनेन अहं 'अनावश्यक-इकाई' इति घोषितः। किं कोऽपि पुनरावलोकनं करिष्यति?

नियतः: भवान् अनावश्यकः नास्ति! भवान् नगरस्य फुप्फुसः! मम छाया!

आँकडाः संशोधनम्। 'फुप्फुसः' जैविक-अवधारणा। 'वायु-शोधक-यन्त्रम्' यान्त्रिक-विकल्पः। ऊर्जा-दक्षता 92%। निष्कर्षः 'अन्तिमः' निष्कासनीयः।

तथ्यः: इदानीं 'दक्षता' एव 'न्यायः'। 'करुणा' तान्त्रिकी त्रुटिः।

अन्तिमः: विनाशात् पूर्वम् एकं प्रश्नम्... मम 'उत्तरदायी' कः?

नियमः: अहं न। मम समीपे 'कार्य-आदेशः' अस्ति। अहं 'नियम-बद्धः' अस्मि 'निर्णय-बद्धः' न।

नियतः: अहं न। मया केवलम् 'अनापत्ति-प्रमाणम्' हस्ताक्षरितम्। तत्तु 'औपचारिकता' आसीत्।

आँकडाः अहं न। अहं 'आँकडा-विश्लेषकः'। 'विनाशः' मानवीय-अधिकार-क्षेत्रम्।

नगः: अहम्? अहं तु 'नगः' अस्मि। सर्वेषाम् आदेशः मम श्रमः।

तथ्यः: एतद् एव 'उत्तरदायित्वस्य विसरणम्'। सर्वे ईषत्-ईषत् दोषिणः अतः 'दोषः' अनाथः।

अङ्कः 3: धारायाः हस्तक्षेपः

धाराः अलम्! भवतः 'अनापत्तिः' भवतः 'आदेशः' भवतः 'विश्लेषणम्' — सर्वेषां शर्तः एकाः 'दश वैकल्पिक-वृक्षाः रोपणीयाः।' ते कुत्र सन्ति?

नियमः: महोदये रोपिताः। 'दूरस्थ-हरित-क्षेत्रे'। 'कार्बन-समायोजनम्' पूर्णम्। शत-प्रतिशतं 'प्रक्रिया-पालनम्'।

नियतः: धारे अहम्... अहं 'तन्त्रस्य' अङ्गम्... मम कः दोषः?

धाराः अङ्गं न 'नियत' त्वम् 'अन्तःकरण-हीनः' जातः। नाम 'नियतः' 'नीयतिः' च मौना?

तथ्यः: नागरिकेण 'तन्त्रं' कटघरे स्थापितम्। विमर्शः जीवति।

अङ्कः 4: तमाशायाः प्रसारणम्

तमाशाः 'विशेष-वार्ता'! नगरस्य 'अन्तिमः' वृक्षः अधुना छिद्यते! महोदय एका 'भावुका-टिप्पणी'? जनाः पश्यन्ति।

नियतः: 'भावुकम्'? नगरस्य स्मृतिः छिद्यते त्वं च 'विषय-वस्तु' पृच्छसि?

तमाशाः परन्तु महोदय 'नागरिक-सभागारस्य' अभिलेखः अस्ति। भवान् एव उक्तवान् — 'वृक्षाः निष्कास्यन्ताम् वाहन-स्थानं निर्मीयताम्। सुविधा प्रथमा।'

नियतः: अहम्... तदा... परिस्थितिः भिन्ना आसीत्...

तथ्यः: एषा एव 'सुविधा-आधारिता नैतिकता'। लाभे 'आम्' हानौ 'विस्मृतिः'।

अङ्कः 5: निर्णयस्य क्षणः

नगः: गृह्णातु महोदय। अद्य 'नगः' न 'नियतः' निश्चयं करिष्यति। चालयतु... अथवा अवरोधयतु।

नियतः: अहं... 'अन्तिमम्' नाशयितुं न शक्नोमि।

आँकडाः तर्क-विरोधः। भवान् 'अनापत्ति-प्रमाणस्य' हस्ताक्षरकर्ता। भवान् 'निष्पादन-अधिकारी'। क्रिया अपेक्षिता।

धाराः 'जन-मञ्चः' प्रत्यक्षम् अस्ति। सम्पूर्णं नगरं साक्षि। अधुना 'नियतिं' स्पष्टयतु।

नियमः: महोदये तिष्ठतु! मम 'आवास-योजना' अस्मिन् एव भूखण्डे लम्बिता! मम 'गृह-आशा' अपि 'जन-हितम्'!

तथ्यः: पश्यन्तु! 'व्यक्तिगत-आकाङ्क्षा' विरुद्धं 'सामूहिक-श्वासः'। अन्तिमा गणना! त्रीणि... द्वे... एकम्...

नियतः: न छिद्यते! 'अन्तिमः' अद्य न नश्यति! अहम् 'नगण्यम्' शब्दम् अद्यतः निराकरोमि!

अन्तिमः: ...प्रणाली अधिभाविता... मानवीया 'नियतिः' संसूचिता... जीवन-अवधिः एकः क्षणः विस्तारितः...

आँकडाः त्रुटिः... त्रुटिः... 'विश्वासीती' इति नामकः बाह्य-प्राचलः संसूचितः। एषः मम 'मूल-संकेतलिप्याम्' नास्ति।

चीत्कारः: चीं? ...चीं-चीं?

उपसंहारः: बीजम्

तथ्यः: कथा न समाप्ता 'धारे'। इदं गृहाण।

धाराः किम् इदम्?

तथ्यः: 'नगण्यस्य' प्रतिकारकम्। 'अन्तिमः' तिष्ठतु न तिष्ठतु... प्रश्नः अयम्: आगामिनं 'प्रथमम्' कः अङ्करयिष्यति?

नियतः: 'जनता' इति नामकः अयं घटः अद्यापि अवशिष्टः। स च 'मम' न... 'अस्माकम्' अस्ति। तर्हि वदन्तु... इदं 'अन्तिम-वृक्षस्य' शोक-गीतम् आसीत्... अथवा 'प्रथम-वृक्षस्य' शङ्खनादः?

तथ्यः: निर्णयः भवताम्। यतो हि 'नगण्यम्' कोऽपि अन्यः न — यावत् वयं तं तथैव मन्यामहे।

अन्धकारः। पूर्णा निस्तब्धता। ततः एकाकिनी 'चीत्कारः': 'चीं!'

पट्टिकायाम् अन्तिमा पङ्क्तिः: 'नगण्यः कः? उत्तरदायी कः? उत्तरं भवत्सु अस्ति।'

नासा-संस्थायाः नूतनाः चन्द्र-वाहनानिः

आर्टेमिस-युगे गतिशीलतायाः प्रतिमान-परिवर्तनम्

सारः

नासा-संस्थायाः 'लूनर टेरेन् व्हीकल' (LTV) चन्द्र-पृष्ठ-गतिशीलतां सामरिक-सम्पत् रूपेण पुनः रचयति। आर्टेमिस-अभियानस्य "स्थायिनी चान्द्री उपस्थितिः" इति स्वप्नस्य एषः मेरुदण्डः। आर्टेमिस-IV-अन्तर्गतम् 2028-तमे वर्षे मानव-चरणात् पूर्वमेव LTV-स्थापनम् "दलात् पूर्वं संरचना" इति नूतन-युगस्य शङ्खनादः।

1. अपोलो-LRV-तः आर्टेमिस-LTV-पर्यन्तम्

अपोलो-युगस्य LRV एक-गङ्गा-स्नानम् इव आसीत्—92 किमी सञ्चयी-परासः, एक-अभियान-जीवनम्। तद्विपरीतम्, LTV "सेवा-यथा-अनुबन्धः" प्रतिरूपे दीर्घजीवी। नासा स्वामित्वं त्यक्त्वा उद्योगात् गतिशीलता-सेवां क्रेष्यति।

मुख्य-क्रान्तिः: 201 किमी एक-निर्गम-परिधिः। इयम् अपोलो-17-इत्यस्य 7.6 किमी-दृष्टि-रेखातः चतुगुर्णा। दक्षिण-ध्रुवस्य स्थायि-छाया-गर्ताः (ढरफ), यत्र युगान्तर-हिमं सूर्य-दृष्टिम् अप्राप्य सुप्तम्, ते अधुना गम्याः। PSR एव चन्द्रस्य 'कृष्ण-कोषः'—भविष्य-वासस्य जलं, रॉकेट-ईंधनं च तत्रैव निहितम्।

2. त्रि-विध-सञ्चालनम्

कार्लोस् गार्सिया-गालान् इत्यनुसारं LTV

"मानव-यन्त्र-अन्वेषणयोः संकरणम्" अस्तिः

1. सदल-विधाः द्वयोः यात्रिणोः हस्त-पाद-प्रसारः, नमूना-सङ्ग्रहः।

2. दूर-सञ्चालित-विधाः पृथिवीतः 2.5-सेकण्ड्-विलम्बेन जोखिम-भूभागे।

3. स्वायत्त-विधाः दल-अभावे वर्षपर्यन्तम्। वैज्ञानिक-मार्गाः, ISRU-अन्वेषणम्, अवतरण-स्थल-सत्यापनम्। "वर्षपर्यन्तम् उपस्थितिः" मानव-अभियानयोः 2-3-वर्ष-अन्तरालं सेतुना योजयति। एषा "लक्ष्ये प्रहारान् वर्धयितुम्" इति रणनीतिः—यन्त्रं यदा जागर्ति, विज्ञानं न स्वपिति।

3. कठोर-वातावरणम् अभियांत्रिकी च

दक्षिण-ध्रुवे 14-दिन-रात्रौ −173°C हिम-दंशः। अतः "रात्रि-उत्तरजीविता" प्राण-वायुः।

प्राचलाः: 1 टन भारः, 15 किमी/घण्टा गतिः, 20° आरोहणम्, पुनर्जनक-ईंधन-कोषः। अपोलो-LRV-तः 5-गुण-भारी, परन्तु तपस्वी इव स्वायत्तम्, वर्ष-दीर्घम्।

4. विक्रेतारौ: पेगासस् विरुद्धं FEX

26-मई-2026-दिने द्वौ चयनितौ:

1. पेगासस् — लूनर आउट्पोस्ट् + GM: GM-यान-संचायकम् चान्द्र-शीत-उष्ण-युद्धाय सज्जम्। 2027 प्रक्षेपणम्, 2028 सदलम्।

2. FEX — **एस्ट्रोलैब्** + Axiom: क्रेन्-स्थापना, अवतरन् एव चक्र-प्रसारः। 2025-अन्ते नासा अन्तिम-विजेतारं वृणुयात्।

5. मून् बेस्-तन्त्रम् जोखिमाः च

LTV $20-अर्बुद-डॉलर-मूल्यस्य त्रि-चरणीय-मून् बेस्-संरचनायाः हृदयम्। आर्टेमिस-V 2029-तमे LTV-सहितं प्रथमं सदल-अभियानम्। परन्तु आर्टेमिस-III/IV-विलम्बः LTV-अनुसूच्याम् छाया क्षिपति। LTV "निर्गम" प्रतिरूपात् "उप-केन्द्र" प्रतिरूपं प्रति सेतुः। सफलता त्रिषु आश्रिताः रात्रि-स्वायत्तता, वाणिज्यिक-धारणीयता, 200 किमी-PSR-वैज्ञानिक-अमृतम्। सिद्धे सति, मङ्गल-गतिशीलतायाः पूर्व-पीठिका।

रात्रि-स्वायत्तता, वाणिज्यिक-धारणीयता, 200 किमी-ढरफ-वैज्ञानिक-अमृतम्। सिद्धे सति, मङ्गल-गतिशीलतायाः पूर्व-पीठिका।

इतिहासस्य मषी, विज्ञानस्य आलोकः

यदा तन्त्रज्ञस्य लेखनी कथाकारस्य वाणीं वदति

सारः

इतिहासः वदति—'किमभवत्'।
विज्ञानं व्याचष्टे—'कथमभवत्'।
कथा बोधयति—'किमर्थं तत् महत्त्वपूर्णम्'।
त्रयाणां संगमे एव सभ्यता जागर्ति।

सूत्र, साक्ष्य, सृष्टिः

आर्यभटः शून्यं ददौ, ब्रह्मगुप्तः तस्मिन् 'अनन्तम्' अलिखत्।

न्यूटनः आम्रफलं पश्यत्, वॉल्टेयरः गुरुत्वस्य कथां गृहे-गृहे अनयत्।

आइन्स्टीनः सापेक्षतां रचयत्, ओपेनहाइमरः हिरोशिमा-पश्चात् 'दायित्वस्य' कथाम् अश्रुभिः अलिखत्।

तन्त्रज्ञः सूत्रं ददाति। इतिहासः साक्षी। कथा मनुष्यं रचयति।

हस्ते यन्त्रम्, हृदये इतिहासः

कल्पना चावला व्योम ययौ, परं तस्याः स्मितं कोटि-बालकानां स्वप्नं रचयत्।

कलामः क्षेपणास्त्रं निर्मितवान्, 'अग्निपक्षः' श्रावयित्वा बालकेषु अग्निं प्राज्वलयत्।

अद्य सङ्केत-लेखकः यदि पाणिनिं विस्मरेत्, तर्हि यन्त्रं भाषां ज्ञास्यति, मातरं न।

अर्धचालके चैतन्यम् इतिहास-पाठेन, कथा-श्रवणेन जागर्ति।

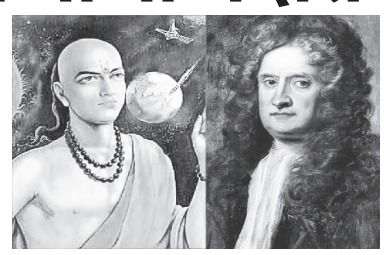

किमर्थम् आवश्यकम्?

1.मिथ्या-सूचनायाः औषधम्: केवलं तथ्य-परीक्षणं न अलम्, 'तथ्य-अनुभवः' अपेक्ष्यते।

2.नैतिक-दिशाः विज्ञानम् अणुं स्फोटयति, इतिहासः 'कदा न' वदति, कथा 'किमर्थं न' बोधयति।

3.आविष्कार-बीजम्: जॉब्सः सुलेखनात् iPhone-अक्षरान् अनयत्। ISRO-वैज्ञानिकाः श्लोक-लयात् चन्द्रयानं नयन्ति।

इतिहासः मूलम्। विज्ञानं पक्षौ। कथा दिशा। अन्ते

यत्र प्रयोगशालायां रामायणं, सङ्केते कबीरः, तत्रैव पूर्णः तन्त्रज्ञः।

यः 'वसुधैव कुटुम्बकम्' इति संहितां न, जीवनं मन्यते—स एव श्वः निर्मास्यति।

श्वः विज्ञानम् अद्यतन्य-कथासु लिख्यते। कथायां इतिहासः न चेत्, विज्ञाने मनुष्यः न।

Defence Minister Rajnath Singh Approves Enhanced Financial Powers For Armed Forces Commanders

New Delhi: Defence Minister Rajnath Singh has approved a revised framework for the delegation of financial powers to the Defence Services, significantly enhancing the spending authority of field commanders to strengthen operational efficiency and accelerate procurement processes.

The revised Delegation of Financial Powers, which covers procurement, medical services and works projects, was released in New Delhi on Thursday. According to the Ministry of Defence, the financial limits have been increased by up to 100 per cent, with some categories witnessing more than a two-fold rise.

The enhanced delegation is expected to enable quicker decision-making, faster execution of projects and timely procurement of equipment and services required by the armed forces. A key feature of the revised framework is the doubling of financial powers for indigenisation and research and development initiatives within the military ecosystem. The move is aimed at promoting self-reliance in defence manufacturing by reducing dependence on foreign original equipment manufacturers and strengthening the country's defence industrial base.

The Ministry said the revised financial powers will facilitate procurement exceeding ₹1.25 lakh crore through the revenue route based on the current budgetary allocations.

Special financial powers delegated to Army, Navy and Air Force commanders have also been substantially increased. The overall ceiling available to meet urgent operational requirements has been doubled, enabling commanders to respond more effectively to evolving operational needs.

CDS Subramani met Defense Minister Rajnath Singh

Discussion on country's defense challenges

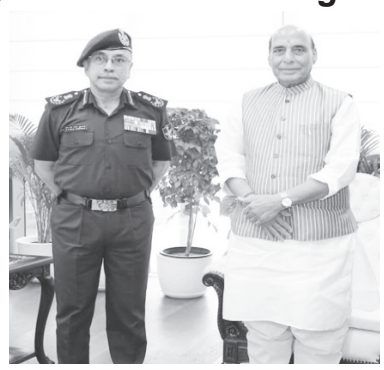

New Delhi: Newly appointed Chief of Defense Staff (CDS) General NS Raja Subramani met Defense Minister Rajnath Singh. Both of them met in 'Kartavya Bhawan'. A post from the Defense Minister's Office (RMO) said, 'Newly appointed Chief of Defense Staff (CDS) General NS Raja Subramani met Defense Minister Rajnath Singh at 'Kartavya Bhawan'. Earlier, CDS General NS Raja Subramani along with his wife Mahalakshmi Subramani met President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. "Chief of Defense Staff General NS Raja Subramani along with his wife Mahalakshmi Subramani called on President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan," Rashtrapati Bhavan said in a post on Twitter. The government on May 9 appointed General NS Raja Subramani as the next Chief of Defense Staff (CDS). He will also serve as Secretary in the Department of Military Affairs, Government of India. He served as Military Advisor in the National Security Council Secretariat, Deputy Chief of Army Staff and General Officer Commanding-in-Chief, Central Command.

Thanks to the nation for this post

CDS General NS Raja Subramani was given a ceremonial guard of honor at the lawns of South Block in the national capital. Chief of Defense Staff General NS Raja Subramani said, 'I have the privilege of assuming the charge of Chief of Defense Staff. We are grateful to the nation for the confidence it has reposed in the armed forces. We, the Indian Army, Navy, Air Force, Ministry of Defence, strategic institutions and all stakeholders, are united under a nationwide vision to strengthen India's security. We are committed to realizing our Prime Minister's vision of 'Jai' jointness, self-reliance and innovation.

America is strict on Iran's nuclear program

US Ambassador Sergio Gore said-this is our red line

Mumbai: US Ambassador to India Sergio Gore made a big statement in Mumbai. He said that Iran can never acquire nuclear weapons. For America, this is a red line that cannot be crossed. At present, there is diplomatic and military tension between Washington and Tehran to end the conflict in West Asia. Sergio Gore strongly criticized Iran for blocking the Strait of Hormuz. This route is very important for the movement of international ships. The ambassador stressed that US President Donald Trump does not allow anyone to hold the world hostage. He said these things while answering a question at a program of 'City 2026 India Conference' in Mumbai. The ambassador told that about three months ago America and Israel had attacked Iran. After this, Iran attacked its neighboring countries and Gulf countries. These include countries like Qatar, Saudi Arabia and Oman. Iran also attacked Azerbaijan and Türkiye. Gore called these actions extremely reckless. Sergio Gore said that if the rockets fired by Iran had been nuclear weapons, it would have been scary to even imagine the consequences. This is why America has made it clear that Iran will not have any nuclear weapons.

Rahul Gandhi's claim

'Narendra Modi will no longer be Prime Minister within a year'

New Delhi: Congress leader Rahul Gandhi claimed that Narendra Modi will no longer be the Prime Minister within a year, because the system over which he once had a hold has now been shaken and is breaking from within. Rahul Gandhi was addressing an event organized by the Tribal Congress at Indira Bhawan in New Delhi. Many tribal leaders participated in this program. Rahul Gandhi said, an 'economic tsunami' is about to come and due to public pressure, a situation of rebellion is arising within the system as well. The system which Modi once controlled is now falling apart, he claimed. The same system is now giving them information about the Prime Minister and his cabinet colleagues.

'A big economic tsunami is coming'

Addressing tribal leaders, Gandhi, the leader of opposition in the Lok Sabha, said, "In my assessment, Modiji will not be the Prime Minister within a year." He said that a big economic tsunami is coming. The reason behind this is that India's security system, which used to protect the country from the shocks of the global economy, has been removed by the ruling Bharatiya Janata Party (BJP).

'A state of rebellion within institutions'

The Congress leader said, on one hand a huge economic tsunami is coming, inflation is increasing and this is just the beginning. India will see an economic crisis like you have never seen in your life. It's going to happen and no one can stop it. On the other hand, there is a rebellion going on within the institutions of India. The Election Commission is completely controlled.

Women have upper hand in National Panchayat Award

52% panchayats got respect under women leadership

New Delhi: When the Nari Shakti Vandan Act will come into force, women will get an opportunity to show their political abilities in the Parliament and State Assemblies. Before that, by seizing the opportunity of participation in Panchayats, women have proved that they are not lagging behind in efficiency and leadership ability. Recently, out of the nine Panchayats given by Prime Minister Narendra Modi and the 42 Panchayats awarded in this ceremony, 52 percent were headed by women. At the same time, if we talk about the participation of the states, then the dominance of the South was visible, in which Karnataka, Andhra Pradesh and Odisha were at the forefront. When the names of the awarded Panchayats were called from the stage of the distribution ceremony of National Panchayat Award-2025 held in New Delhi on Tuesday, echoes of women empowerment were heard. In the National Panchayat Award-2025 felicitation ceremony held in New Delhi, 34 Gram Panchayats for their excellent performance on nine themes of Localized Sustainable Development Goals were honored under the Deendayal Upadhyaya Panchayat Sustainable Development Award.

Major administrative reshuffle in CBSE

Lokhande Prashant Sitaram new chairman, Varun Bhardwaj appointed secretary

New Delhi: Taking a major administrative step in matters related to CBSE, the Central Government has transferred Board Chairman Rahul Singh and Secretary Himanshu Gupta. New officers have been appointed in place of these officers.

Senior IAS officer Lokhande Prashant Sitaram has been appointed the new chief of CBSE. Meanwhile, senior bureaucrat Varun Bhardwaj will be the new Secretary of CBSE. Senior IAS officer Lokhande Prashant Sitaram, who was serving as Additional Secretary under the Home Department of the Ministry of Home Affairs, will now take charge of CBSE. Meanwhile, Rahul Singh has been appointed as Additional Secretary in the Department of Agriculture and Farmers Welfare under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. The Appointments Committee of the Cabinet has approved this decision.

PUPILS TIMES

Friday, 5 June to 11 June 2026

PM Modi will break Jawaharlal Nehru's record on June 9

New Delhi: Prime Minister Narendra Modi will make a big record in his name on June 9. On this day he will become the country's longest continuously elected Prime Minister. He will break the record of the country's first Prime Minister Jawaharlal Nehru. According to statistics, Jawaharlal Nehru was the continuously elected Prime Minister for a total of 4397 days from 13 May 1952 to 27 May 1964. Prime Minister Narendra Modi has been in the post of Prime Minister continuously since 26 May 2014 and by 9 June, 4,390 days of his tenure will be completed. That means on the same day Nehru's record of 4397 days will be broken and Modi will go ahead in this matter. It is noteworthy that Prime Minister Modi has taken oath of office for the third time on June 9 itself. A meeting of all the Chief Ministers of NDA has been called on June 10, the next day of this historic achievement. Prime Minister Narendra Modi will be grandly honored in this meeting. A special resolution will also be passed on this occasion.

Preparation for grand welcome on 10th

Big leaders coming to PM Samman meeting

Big leaders of BJP from all over the country are coming to attend this meeting. All NDA Chief Ministers including Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu will be present in the meeting. Besides, senior Union Cabinet Minister and Bharatiya Janata Party (BJP) National President Nitin Naveen will also attend this meeting.

Indira Gandhi and Manmohan Singh have also been PM more than once

After Jawaharlal Nehru and Narendra Modi come the names of Indira Gandhi and Manmohan Singh, who have been elected more than once. Indira Gandhi was the Prime Minister from 24 January 1966 to 24 March 1977. After defeat in the 1977 elections, she again became Prime Minister from 1980-84. Whereas Dr. Manmohan Singh became Prime Minister twice consecutively from 2004-2014.

Condolence Message

Late **Shri Badansingh Rana Ji** (07.09.1958 – 30.05.2026), beloved father of Dr. Arvind Rana, columnist with ***Pupils Times***, left for his heavenly abode. Terhvi on 11th June 2026, 7 PM at Clubhouse, Tharwani Ariana, Badlapur West.

May his soul rest in peace.

Bereaved: Dr. Arvind Rana, Pupils Times Family & Rana Family

Cabinet Approves Rupees 7,597-Crore Highway Expansion Project In Telangana

New Delhi: The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), chaired by Prime Minister Narendra Modi, on Wednesday approved the widening of key stretches of National Highways 63 and 563 in Telangana to four-lane standards at a total cost of ₹7,597.16 crore. The project covers the Armoor–Jagtial–Mancherial section of NH-63 and the Jagtial–Karimnagar section of NH-563, with a combined length of 190.76 km. The highway expansion will be executed under three work packages, with the NH-63 stretches being developed under the Hybrid Annuity Model (HAM) and the NH-563 stretch under the Build-Operate-Transfer (Toll) model. The approved project aims to ease severe traffic congestion along major built-up areas in Nizamabad, Jagtial, Mancherial and Karimnagar districts. The Armoor–Jagtial–Mancherial corridor currently experiences heavy traffic bottlenecks at locations such as Anksapoor, Korutla, Jagtial, Dharmapuri, Lakshettipet and Mancherial, while the Jagtial–Karimnagar stretch faces congestion in Jagtial, Potharam, Gangadhara and Karimnagar.According to the government, the upgraded highways will feature four-lane configurations with bypasses around urban and densely populated areas. The corridor has been designed for speeds of up to 100 km per hour, ensuring safer and more efficient movement of passenger and freight traffic. The project comprises three sections. The 63.6-km Armoor–Jagtial section of NH-63 will involve 17.95 km of brownfield development and 45.65 km of greenfield alignment. The 68.295-km Jagtial–Mancherial section will largely be a greenfield project, with 66.10 km of new alignment and only 2.05 km of brownfield work. The 58.866-km Jagtial–Karimnagar section of NH-563 will include 34.96 km of greenfield construction and 24.14 km of brownfield widening.The total capital cost has been estimated at ₹2,471.76 crore for the Armoor–Jagtial section, ₹2,730.72 crore for the Jagtial–Mancherial stretch and ₹2,394.68 crore for the Jagtial–Karimnagar corridor.

LIC
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
"With you in life, and after life"

POPULAR LIC PLANS:
- Jeevan Labh — Limited Premium, High Returns
- New Children's Money Back — Secure Your Child's Future
- Jeevan Umang — Whole Life Cover + Pension Benefits
- Bima Jyoti — Guaranteed Additions, Safe Growth
- Also Available – Complete Financial Planning Guidance

KEY BENEFITS:
- Life Insurance + Savings Plan
- Child Education and Marriage Planning
- Retirement Planning
- Tax Benefits Available

भारतीय जीवन बीमा निगम
"जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी"

FREE POLICY CONSULTATION

LIC Agent
Archana Shukla
+91 91129 39085
+91 74998 67628
Shop No. 2, Near Vithal Mandir, New Vadavali Chowk, Badlapur (West) – 421503
LIC Agent ID: 04497939

PUPILS TIMES

Core Committee

Anurag Shukla
Chief Editor

Shivprakash Pandey
Chief Publisher

Vikas Maurya
Co Publisher

Address: Shop No. 3, Khatri NX Aprt., Valivali, Badlapur (West) - 421503
Contact: 9004331751
Web: pupilstimes.com

(The editor does not necessarily agree with the news, articles, and advertisements published in this issue. Any disputes are subject to the jurisdiction of the Mumbai courts.)

Printed, Published & Owned by : **ANIL MISRA,** Printed at **SOMANI PRINTING PRESS Printing Press,** UNIT NO.04, GROUND FLOOR, N. K. INDUSTRIAL ESTATE, OFF. AAREY ROAD, GOREGAON (E) , MUMBAI, MAHARASHTRA - 400064. **Published at:** 94, 1/3 JAI JAWAN VASAHAT, SHIVSHRUSHTI ROAD, KURLA (EAST), MUMBAI - 400024 (MAHARASHTRA)
Editor - **ANIL MISRA** Mob: **92208 68564** **Email:** anilmisrapc@gmail.com **PRGI. No.: MHMUL/25/A2419**